भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 676

बुधवार, 26 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-कॉमर्स नीति

676. डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ई-कॉमर्स नीति में कुछ बदलाव किए हैं ताकि स्वदेशी व्यापारियों और व्यापारिक घरानों को ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा अनुचित लाभ उठाने से बचाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस नीति बदलाव से अमेरिकी व्यापारी खुश नहीं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ मीडिया की यह रिपोर्टों के अनुसार इन परिवर्तनों से ई-कॉमर्स की मात्रा में कमी आएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ई-कॉमर्स उद्योग के विनियमन और विकास के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (घ): राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे आम लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। यह नीति ई-कॉमर्स इकोसिस्टम के 6 व्यापक क्षेत्रों नामत: आंकड़े; अवसंरचना विकास; ई-कॉमर्स बाजार; विनियामक मुद्दे; घरेलू डिजीटल अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन और ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात संवर्धन संबंधी मुद्दों का समाधान करती है। इस नीति में, सभी हितधारकों, चाहे वे निवेशक हों, विनिर्माता, एमएसएमई, व्यापारी, खुदरा विक्रेता, स्टार्टअप और उपभोक्ता हों, के हितों को ध्यान में रखा गया है।

तथापि, ई-कॉमर्स पर एफडीआई नीति, जिसे पहली बार वर्ष 2000 के प्रेस नोट-2 के माध्यम से घोषित किया गया था, में बी2बी ई-कॉमर्स गतिविधियों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। पहले से मौजूद नीतिगत ढांचे को स्पष्ट करने के दृष्टि से, पणधारकों से गहन विचार-विमर्श करने के पश्चात, वर्ष 2016 में डीआईपीपी द्वारा प्रेस नोट 3 जारी किया गया था। बी2सी ई-कॉमर्स, जो कि इंवेंटरी आधारित मॉडल के माध्यम से मल्टी ब्रांड खुदरा बिक्री है, में इस दौरान एफडीआई पर निषेध है। 26 दिसंबर, 2018 को जारी प्रेस नोट 2 (2018) के माध्यम से सरकार ने पहले से मौजूद सिद्धांत में कोई परिवर्तन किए बिना, सिर्फ नीति का अक्षरश: कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत प्रावधानों को दोहराया है।

(ख): मसौदा नीति के उत्तर में, कई विदेशी सरकारों से टिप्पिणयां प्राप्त हुई हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसाय जुड़े मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की टिप्पणी शामिल है।

(ग): ऐसी कोई रिपोर्टें उपलब्ध नहीं हैं।

*****